• आदेश...

जो करेगा अच्छा काम,उसे ही मिलेगा सम्मान

शिमला : युवा जब भी कोई बड़ी परीक्षा के लिए जाते हैं तो उनके मन में नेगेटिव मार्किंग का डर होता है। यही डर उन्हें बेहतर परफॉर्म करने के लिए प्रेरणा भी देता है। हिमाचल में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने सरकारी अफसरों व कर्मचारियों के मन में अब लक्ष्य प्राप्ति के लिए काम करने का सार्थक डर बैठाने का प्रयास किया है। अब सालाना गोपनीय रिपोर्ट यानी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जिसे सरकारी सेक्टर में एसीआर के नाम से अधिक जाना जाता है, को बेहतर बनाने के लिए लक्ष्य हासिल करना होगा।

अब होगी न्यूमेरिकल ग्रेडिंग

अब यूं ही एसीआर बेहतर नहीं होगी। इसके लिए सरकार की तरफ से तय किए गए लक्ष्यों को हासिल करना होगा। यही नहीं, परफॉर्मेंस की दौड़ की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब सालाना गोपनीय रिपोर्ट में पहले की तरह गुड, वेरी गुड या आउटस्टैंडिंग नहीं लिखा जाएगा। इसके बदले न्यूमेरिकल ग्रेडिंग होगी। यानी एक से लेकर दस तक नंबर दिए जाएंगे। इसी तरह कर्मचारियों के लिए एपीआर यानी एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट में भी न्यूमेरिकल व्यवस्था होगी। इससे सरकारी कामकाज में सुधार आएगा और लक्ष्य हासिल करने के लिए काम का दबाव भी बनेगा।

एसीआर से नंबर भी कटेंगे

यदि अफसरों ने तय लक्ष्य हासिल नहीं किए तो एसीआर में नंबर काटे जाएंगे। इससे न केवल प्रमोशन बाधित होगी, बल्कि वेतन वृद्धि में भी रुकावट आएगी। सरकार के सभी विभागों के लिए एक साल का प्लान तैयार होगा। उसमें अफसरों व कर्मचारियों के लिए लक्ष्य रखे जाएंगे। शिक्षा विभाग का उदाहरण लें तो वहां प्रधानाचार्यों की एसीआर में रिजल्ट व स्कूल की ओवरऑल परफॉर्मेंस काउंट की जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ने इसके लिए सारी नियमावली बना दी है। कैबिनेट में सारा केस डिस्कस हो चुका है और अब सिर्फ नोटिफिकेशन का इंतजार है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार के इसी कदम पर अपने बयान में कहा कि इससे सरकारी सेक्टर की कार्यकुशलता बढ़ेगी। अफसरों व कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय होगी। साथ ही विकास कार्यों के लक्ष्य समय पर हासिल करने में सफलता मिलेगी।

• स्वतंत्रता दिवस...

पेंशनरों-कर्मियों के लिए सीएम की घोषणा, एरियर मिलेगा

● पंकज/ देहरा

हिमाचल प्रदेश का राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह देहरा में शहीद भुवनेश डोगरा मैदान में आयोजित किया गया। जिला कांगड़ा के देहरा में शहीद भुवनेश डोगरा मैदान में पहली बार राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम ने देहरा में राज्य विद्युत बोर्ड का अधीक्षण अभियंता कार्यालय, जल शक्ति विभाग का अधीक्षण अभियंता कार्यालय और खंड चिकित्सा कार्यालय खोलने की घोषणाएं कीं। उन्होंने वन अधिकार अधिनियम के तहत पौंग बांध विस्थापितों के स्वामित्व के दावों का समाधान करने की भी घोषणा की। उन्होंने 10 ग्राम पंचायतों में 500 किलोवाट तक की क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करके उन्हें हरित पंचायत में परिवर्तित करने की भी घोषणा की।

सीएम सुक्खू ने 75 वर्ष और इससे अधिक आयु के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन एरियर का इस वित्त वर्ष में पूरा भुगतान करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रयासरत है और आगामी वर्षों में कर्मचारियों और पेंशनरों की देनदारियों का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 15 हजार जीएसटी विरासत मामलों के समाधान के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी ताकि प्रभावितों को राहत मिल सके। प्रदेशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार अथक प्रयासों के साथ प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सुधारने में लगी हुई है और इस दिशा में बहुत कुछ हासिल भी कर लिया गया है। वित्तीय चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हित में कई फैसले लिए हैं। राज्य सरकार की नीतियों से प्रदेश को एक वर्ष में 2200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है।

सुख शिक्षा योजना में 1000 रुपये की मासिक सहायता की घोषणा

सीएम सुक्खू ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत एकल महिला परिवारों, निराश्रित महिलाओं, विधवाओं और विकलांग माता-पिता के 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए 1000 रुपये की मासिक सहायता की घोषणा की। सरकार इन बच्चों का आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेजों और पीएचडी कार्यक्रमों में 27 वर्ष की आयु तक की शिक्षा का खर्च भी वहन करेगी। यदि नि:शुल्क छात्रावास आवास उपलब्ध नहीं है, तो राज्य सरकार पीजी आवास के लिए 3000 रुपये प्रतिमाह की सहायता भी प्रदान करेगी।

धनबल से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र रचा गया

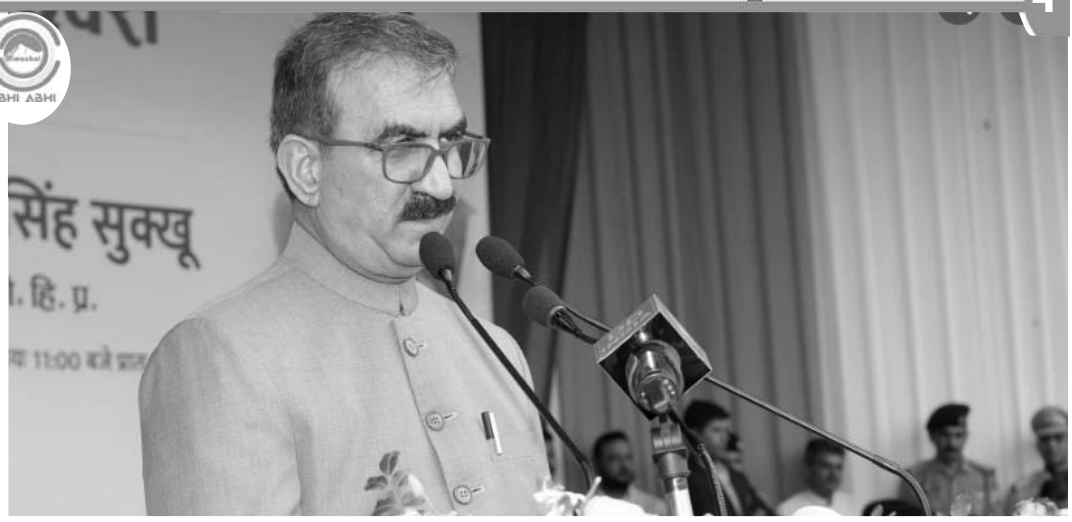

सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मेजर सोमनाथ शर्मा को देश का पहला परमवीर चक्र प्राप्त होने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा सहित चार परमवीर चक्र विजेता, दो अशोक चक्र, 11 महावीर चक्र और 23 कीर्ति चक्र विजेता हैं, जोकि गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार को अपने 20 माह के छोटे से कार्यकाल में राजनीतिक, आर्थिक, और प्राकृतिक आपदा के मोर्चे पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि धनबल के जरिये लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र रचा गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश पर उपचुनावों का बोझ डाला गया और चार माह तक प्रदेश के विकास कार्यों को ठप करने की साजिश रची गई, लेकिन प्रदेश की प्रबुद्ध जनता से इन साजिशों को नाकाम किया। लोगों ने प्रदेश सरकार पर भरोसा जताते हुए धनबल पर जनबल की ताकत दिखाते हुए लोकतंत्र को बरकरार रखा।

हिमकेयर योजना को बंद नहीं किया

उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के गलत निर्णयों के कारण प्रदेश पर हजारों करोड़ रुपये का बोझ डाला गया, जिसके कारण वर्तमान सरकार को गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए बिजली और पानी के बिल माफ कर दिए गए, जिसके कारण एक वर्ष के भीतर ही राज्य विद्युत बोर्ड पर 780 करोड़ रुपये और जलशक्ति विभाग पर 300 करोड़ रुपये का बोझ पड़ गया। इसके अलावा हिमकेयर योजना में अनुचित लाभ लिए जाने के मामले सामने आने के बाद निजी अस्पतालों को इस योजना से बाहर किया गया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हिमकेयर योजना को बंद नहीं किया गया है। सभी सरकारी अस्पतालों में लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा और निजी अस्पतालों में भी डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य चयन आयोग ने 2,983 पदों में से 1,841 पदों का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है।

लंबित भर्तियों के परिणाम जल्द घोषित होंगे, आपदा प्रभावितों के लिए राहत पैकेज

सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने जेओए (आईटी) 817 के अभ्यर्थियों के लिए मजबूती से अपना पक्ष रखा और न्यायालय के फैसले के बाद चार साल से लंबित भर्ती का परिणाम घोषित किया। उन्होंने कहा कि अन्य लंबित भर्तियों के परिणाम जल्द घोषित करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बरसात के मौसम में हुए भारी नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि सभी प्रभावित लोग उनके परिवार के सदस्य की तरह हैं। सरकार हर प्रभावित परिवार के पुनर्वास और उन्हें तत्काल राहत के लिए प्रतिबद्ध है। आपदा प्रभावित हर परिवार को 50 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों के परिवारों को 10 हजार रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को तीन महीने के लिए मकान किराये के लिए पांच हजार रुपये दिए जा रहे हैं। प्रभावित परिवारों को मुफ्त राशन, गैस, बर्तन, बिस्तर और सिलिंडर भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा प्रभावित परिवारों की मुश्किलों को कम करने के लिए जल्द ही विशेष राहत पैकेज की घोषणा की जाएगी।

42 दवाइयां मुफ्त में उपलब्ध करवाई जा रहीं

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपना चुनावी वादा पूरा करते हुए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये और सालाना 18 हजार रुपये की सम्मान राशि दी जा रही है। इसके अतिरिक्त पूर्व में अन्य पेंशन योजनाओं का लाभ ले रही 2.37 लाख महिलाओं को इस योजना में शामिल कर उनकी मासिक पेंशन 1500 रुपये की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। कैंसर मरीजों का निशुल्क उपचार और 42 दवाइयां मुफ्त में उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त टांडा मेडिकल कॉलेज में विभिन्न श्रेणियों में विशेषज्ञ डॉक्टरों और चिकित्सा अधिकारियों के 462 पद और आईजीएमसी शिमला व अटल मेडिकल सुपर स्पेशलिटी संस्थान चमियाना में 489 पद भरे जा रहे हैं।

सेब उत्पादकों के 153 करोड़ की देनदारियों का भुगतान किया

सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि इस वर्ष से यूनिवर्सल कार्टन की व्यवस्था लागू की गई है। मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब उत्पादकों के 153 करोड़ रुपये की देनदारियों का भुगतान किया गया है, जिसमें से 90 करोड़ रुपये पूर्व भाजपा सरकार की देनदारियों के चुकाए गए हैं। सेब, आम और नींबू प्रजाति के फलों का समर्थन मूल्य 12 रुपये प्रति किलो तय किया गया है।

संस्थाओं और शख्सियतों को किया सम्मानित

सीएम ने कई संस्थाओं और शख्सियतों को विशिष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया। डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन विभाग को सिविल सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद के महानिदेशक डॉ. राकेश कुमार, दिव्य मानव ज्योति सेवा ट्रस्ट के संस्थापक सत्य प्रकाश शर्मा और प्रो. महेश वर्मा को प्रेरणा स्रोत सम्मान प्रदान किया गया। केहर सिंह ठाकुर, प्रो. केशव राम शर्मा और पूनम ठाकुर को हिमाचल गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया।

सीएम सुक्खू ने 75 वर्ष और इससे अधिक आयु के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन एरियर का इस वित्त वर्ष में पूरा भुगतान करने की भी घोषणा की।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रयासरत है और आगामी वर्षों में कर्मचारियों और पेंशनरों की देनदारियों का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा...

• ऊना में...

भारी बारिश से नुकसान

ऊना : भारी बारिश के चलते ऊना जिला में भारी नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जिला मुख्यालय से संतोषगढ़ वाया रामपुर होकर जाने वाले रोड पर रामपुर में एक पुल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया जिसके चलते यातायात को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। वहीं पुल क्षतिग्रस्त होने के चलते लोगों को जाम से भी दो-चार होना पड़ रहा है। भारी बारिश के कारण कई जगहों पर सड़के दरक गई है, जबकि पेड़ गिरने के चलते भी मार्ग अवरुद्ध हुए हैं। शनिवार तड़के सब्जी मंडी आने वाले दो किसान क्षतिग्रस्त पुल पर बुरी तरह गिरे जिसके बाद यह मामला सबकी नजर में आया। तुरंत घटना को लेकर प्रशासन को सूचित किया गया जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने भी मौके पर पुलिस और होमगार्ड के जवान भेज कर इस मार्ग को पूरी तरह बंद करवाया। ऊना-संतोषगढ़ रोड के बंद होने पर वैकल्पिक मार्ग से यातायात को सुचारू करने का प्रयास किया गया। दूसरी तरफ ऐतिहासिक और प्राचीन महादेव मंदिर कोटला कलां को जाने वाले मार्ग पर डंगोली में एक बड़ा पेड़ गिरने के चलते रास्ता बंद हो गया है।

• लापता युवक का शव...

धर्मशाला : धर्मशाला के साथ लगते जोगीबाड़ा में एक युवक का क्षत-विक्षत शव पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की पुष्टि करते हुए एएसपी कांगड़ा हितेश लखनपाल ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक अज्ञात शव जोगीबाड़ा के पास पड़ा हुआ है। मृतक की पहचान दीप नारायण, निवासी राम नगर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक पिछले सात-आठ दिन से लापता था।